Inadequate project preparation

Problems in acquisition of land.

Delays in environmental/forest clearance

Delays in finalisation of detailed engineering

Delays in supply of equipments.

Government constantly endeavours to improve the system of project implementation and have taken various measures which include—

Emphasis on preparation of realistic project implementation plan.

Setting up of Task Force|Empowered Committee for problem solving and speedy implementation of projects.

Issue of detailed guidelines to facilite environmental clearance .

Close follow up by concerned Ministries and project authorities with State Governments, equipment suppliers, contractors, consultants and other concerned agencies to minimise delays.

Issue of directions for ensuring continuity of tenure of project head until the completion of project and 2—3 years beyond to ensure accountability for project implementation.

राज्यों में जिलों का विभाजन

2140. **श्री अजीत जोगी :**
श्री पृथ्वी मांझी :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिले को सिद्धांत रूप में एक इकाई मानकर क्या केन्द्रीय सरकार अब इस दृष्टि से यह विचार करेगी कि राज्यों के तुलनात्मक रूप में बहुत बड़े क्षेत्र और आबादी वाले जिलों को छोटे जिलों में विभाजित कर दिया जाये ताकि वहां पर योजना और विकास से संबंधित कार्य को आसानी तथा सुचारू रूप से किया जा सके ;

(ख) क्या राज्य-सरकारों ने जिलों के पुनर्गठन के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजे हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) बड़े जिलों को छोटे जिलों में विभाजित करने के लिए बनाये गये मध्यप्रदेश के जिला पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के संबंध में केन्द्रीय सरकार का क्या रवैया है ?

योजना मंत्री तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) जिला आयोजन से संबंधित कार्यकारी दल की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि "केवल प्रशासनिक आधार पर ही जिले का आकार भी अधिक प्रबंधकीय बनाया जाना चाहिए।" तथापि, जिलों के विभाजन का विषय राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आता है ।

(ख) जी, नहीं । योजना आयोग में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है ।

(घ) यह प्रश्न मध्यप्रदेश सरकार से संबंधित है ।

संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किये गये मरीजों का डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में इलाज

2141. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्यों द्वारा भेजे गये मरीजों को डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के विभिन्न चिकित्सा विभागों में प्राथमिकता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजनार्थ डाक्टरों की अलग से भी कोई व्यवस्था है ; यदि हां, तो , प्रत्येक विभाग में उनके नाम तथा टेलीफोन नं० क्या-क्या हैं ; और

(ग) आपात स्थिति के समय ऐसे मरीजों के इलाज के लिए किस अधिकारी से सम्पर्क किया जाना चाहिए ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसे मरीजों को ओ.पी.डी. के समय के दौरान ओ.पी.डी. के ड्यूटी पर तैनात संबंधित विशेषज्ञ के पास भेज दिया जाता है। ऐसे मरीजों को जब ओ.पी.डी. के समय के बाद आपातकालीन विभाग में भेजा जाता है, डा० (श्रीमती) मीना भाटिया, मुख्य चिकित्सा अधिकारी उनका इलाज करती हैं। उपचर्या गृह में दाखिल किए जाने वाले रोगियों को डा. के. सी. मलिक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। इन अधिकारियों के टेलीफोन नम्बर इस प्रकार हैं :—

1. डा० (श्रीमती) मीना भाटिया मुख्य चिकित्सा अधिकारी —345525/44 (कार्यालय)

2. डा. के. सी. मलिक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी —345525/479 (कार्यालय) 350467

Plans to provide jobs for unemployed

2142. SHRI P. N. SUKUL: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether Government have drawn up any plans to provide jobs for the unemployed in order to provide mid-day meals for children;

(b) if so, what are the details thereof and the investments proposed to be made in these schemes; and

(c) by when these schemes are expected to be implemented?

THE MINISTER OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) Government have not drawn up any plan to provide jobs for the unemployed in order to provide mid-day meals for children.

(b) and (c) However, Government has decided to provide more jobs for the unemployed for which an allocation of Rs. 500 crores has been made in the next year's budget. No decision has yet been taken regarding mid-day meals programme.

Task force for new planning methodology

2143. SHRI BASUDEB MOHAPATRA: Will the Minister of PLANNING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Planning Commission has already set up a task force to operationalise the new district level planning; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF PLANNING AND THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI MADHAVSINH SOLANKI): (a) and (b) An internal Task Force was set up mainly for assessing the difficulties in implementation of district level planning. Two areas, namely, need for training of planning personnel and the need to cover the information gap were particularly identified. The relevant details are being looked into and the decisions are expected to be incorporated in the Eighth Plan.